forcibly seized by the Bank from some creditors who did not pay the instalments; and

(c) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) Reserve Bank of India have reported that in the absence of specific complaints they had no occasion to investigate this matter.

(c) Does not arise.

बैंकिंग क्षेत्र में सुधार

2801. **श्री विनोद शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार वर्तमान बैंकिंग प्रणाली में सुधार लाने के लिए एक नया आयोग गठित करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि नवम्बर, 1991 में श्री नरसिम्हम की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन के आधार पर सरकार द्वारा बैंकिंग प्रणाली में अब तक क्या सुधार किए गए हैं ;

(घ) सरकार द्वारा किन-किन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है परंतु उन्हें अब तक कार्यान्वित नहीं किया गया है ; और

(ङ) बैंकिंग प्रणाली के किन-किन पहलुओं को सुधारने के लिए उन्हें प्रस्तावित नए आयोग को सौंपे जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) वित्तीय प्रणाली अध्यक्ष एम नरसिंहम पर समिति का गठन अगस्त 1991 में किया गया था और उसकी रिपोर्ट सरकार को नवंबर 1991 में प्राप्त हुई थी । समिति की सिफारिशों के अनुक्रम में किए गए सुधारात्मक उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं: एस.एल.आर और सी.आर.आर. में कमी, ब्याज दर संरचना का सरलीकरण, पूंजी पर्याप्तता के संबंध में मानकों का निर्धारण, आय की पहचान और प्रावधान संबंधी अपेक्षायें, अधिक सुस्पष्टता के लिए तुलन पत्र और लाभ तथा हानि फार्मेटों का संशोधन, शाखा लाइसेंसिंग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग-निर्देशों में संशोधन, पूंजी बाजार को उदार करने के उपाय, एस.ई.बी.आई को सांविधिक शक्तियां प्रदान करना, विभिन्न म्यूचुअल फण्डों से कर में रियायतों के मामले में एक समान व्यवहार करना आदि । समिति की अन्य सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

(ङ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न पैदा ही नहीं होता ।

Recovery of agricultural loans

2802. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the State Governments are being asked to apply Revenue Recovery Act for recovery of Agricultural loans advanced by Nationalised Banks; and

(b) if so, what is the response of various State Governments thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) An Expert Group on State Enactment having a bearing on commercial banks' lending to agriculture (Talwar Committee) had recommended enactment on legislation by various State Governments and Union Territories on the lines of 'Model Bill' evolved by them for the purpose. In pursuance of the above recommendation, State Governments were advised to enact legislation for speedy recovery of agricultural advances of commercial banks. The following 16 States have already enacted the legislation on the subject: (1) Assam, (2) Bihar, (3) Gujarat (4) Haryana, (5) Himachal Pradesh, (6) Karnataka, (7) Madhya Pradesh, (8) Maharash-